की गई थी, देश के सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में लागू है।

(क) पूर्व मध्य प्रदेश राज्य में यह योजना लागू की गई है। इस योजना के लिये 1992-93 के दौरान मध्य प्रदेश की राज्य सरकार को 4.50 लाख रुपये की एक धनराशि निर्मुक्त की गई थी और 1993-94 के अब तक 6.75 लाख रुपये दिए गए हैं।

औषधीय तथा सुगन्धित फसलों का उत्पादन

3281. **श्री शिव प्रसाद जनपुरिया :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार औषधीय तथा सुगन्धित फसलों के उत्पादन की योजना क्रियान्वित कर रही है; और

(ख) क्या उपरोक्त योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश के जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में एक हर्बल गार्डन और नर्सरी स्थापित करने की एक योजना क्रियान्वित की गई है; यदि नहीं, तो यह कब तक क्रियान्वित की जाएगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, हां। आठवीं पंच-वर्षीय योजना के दौरान सरकार द्वारा 500 लाख रुपए की कुल लागत पर औषधीय और सुगंधित पौधों के विकास की एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) जी, हां। जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर को इस प्रयोजन के लिए निधि निर्मुक्त कर दी गई है और योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है।

गुजरात में खाद्यान्नों का उत्पादन

3282. **श्री जयन्ती भानुशाली :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में वर्ष 1992-93 और वर्ष 1993-94 के दौरान कुल खरीफ मौसम में खाद्यान्नों का जिला-वार उत्पादन हुआ तथा इस संबंध में वर्ष 1994-95 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने गुजरात में खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ग) सरकार द्वारा नई कृषि नीति के अन्तर्गत राज्य के किसानों को उपलब्ध कराई गई सूचना तथा सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) वर्ष 1992-93 में गुजरात में खाद्यान्नों के समग्र उत्पादन को जिलावार दर्शाने वाला एक विवरण (नवीनतम उपलब्ध) संलग्न है। **(नीचे देखिए)** 1993-94 के लिए समान आंकड़े राज्य से अभी देय नहीं हुए हैं। तथापि, वर्तमान आकलन के अनुसार 1993-94 के दौरान सम्पूर्ण गुजरात राज्य में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन लगभग 41.66 लाख मी० टन होने की सम्भावना है। 1994-95 के लिए खाद्यान्नों के उत्पादन लक्ष्यों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) गुजरात में खाद्यान्नों की उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि करने के लिए ये योजनाएं अर्थात्—समन्वित दलहन विकास कार्यक्रम (आई०पी०आर०डी०), विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम (एस०एफ०पी०पी०)—गेहूं और मक्का व कदन्न बीज मिनिकिटों सहित राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना क्रियान्वित की जा रही है।

(ग) और (घ) 14 मई, 1993 को संसद में रखे गए कृषि नीति संकल्प के संशोधित

प्राक्कथ में कृषि विकास और अनुसंधान कार्यक्रमों को भारतीय कृषि में आने वाली चुनौतियां तथा कृषि के विविधीकरण के जरिए कार्यकलापों का सृजन तथा कृषि पर आधारित उद्योगों का संवर्धन करके अर्द्ध-रोजगार, बेरोजगारी और कुपोषण की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया गया है।

कृषि नीति संकल्प के मसौदे का उद्देश्य सहकारी समितियों तथा स्थानीय समुदायों को मजबूत बनाना और पुनः सक्रिय तथा कृषि विकास में गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी में वृद्धि करना है।

विवरण

1992-93 के लिए गुजरात में खाद्यान्नों का जिलेवार कुल उत्पादन

नवीनतम उपलब्ध

जिले	(हजार टन में)
अहमदाबाद	275.7
बनास कांठा	297.6
बड़ोदरा	327.5
भड़ूच	211.2
बलसाड़	254.6
डांग	30.6
गांधीनगर	53.5
जेड़ा	526.6
मेहसाना	360.8
पंच महल	516.0
साबर कांठा	412.8
सूरत	299.4
अमरेली	222.5
भाव नगर	347.5
जाम नगर	158.4
जूनागढ़	392.9
कच्छ	217.8
राजकोट	339.6
सुरेन्द्रनगर	164.7
अन्य	–
कुल	5409.7

Proposl to Stop Crop Production Subsidies

3283. SHARIMATI CHANDRIKA ABHINANDAN JAIN : Will the Minister of AGRICULTURE be pleaseed to state :

(a) whether the Central Government have proposed to stop grant of crop production subsidies running into several crores from the year 1994-95 ;

(b) if so, the reasons for discontinuation in the high productive areas of the country from the current financial year;

(c) whether the Central Government has considered any other scheme to encourage farmers production of foodgrains, cotton and other crops; and

(d) if so the main features of the scheme including the time limit for its implementation by Government ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM) : (a) and (b) Incentives to the farmers by way of subsidies will continue to be provided through various on-going Central Sector/Centrally Sponsored Crop Production Programmes during 1994-95. However, subsidies/incentives are proposed to be withdrawn on some of the inputs under Rice, Wheat and Coarse Cereals Production Programmes from the year 1994-95.

(c) and (d) A scheme for the develop- ment of Sugarcane has been proposed for implementation during the remaining period of the Eighth Five Year Plan. The main features of the scheme are :

Organisation of field demonstrations and training of farmers/farm labourers on improved crop production technology, use of organics, supply of implements etc.

S. N. Banerjee Committee on Pesticides

3284. SHRIMATI CHANDRIKA ABHINANDAN JAIN : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) what are the recommendations made by the S.N. Banerjee Committee on pesti-tides;